Statement-II

Proforma proposals sent for Clarification/ Modification

(Rs. in Lakhs)

Sl No.	Name of Town	Project Cost
1.	Salaya	81.00
2.	Bhanwad	361.00
3.	Ranavav	55.00
4.	Adityana	56.00
5.	Kutiyana	80.00
6.	Vanthali	149.00
7.	Visavadar	72.00
8.	Khedbrahma	71.00
9.	Kheralu	38.00
10.	Chikhali	75.00
11.	Devgadh-Baria	68.00
	TOTAL	1106.00

दिल्ली में निर्धनों के आवास के लिए धनिकों पर करारोपण

1080. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1997 के "पायोनियर" में "टैक्सिंग रिच फार हाउसिंग पुअर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली में धनी लोगों से कर-संग्रहण करके निर्धनों को आवास उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो धनी लोगों की पहचान करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किया है और इस संबंध में कुल कितनी धनराशि वार्षिक रूप से एकत्र करने का लक्ष्य है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ यू.वेंकटेस्वरलू) (क) जी, हां।

(ख) गरीबों की आवास अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए, 7 से 9 अक्टूबर, 1996 तक हुए राष्ट्रीय आवास सम्मेलन ने अन्य के साथ-साथ, विलासमय आवास पर कर लगाने की सिफारिश की है। इसीलिए, राज्य सरकारों से (जी.एन.सी.टी.डी. को शामिल करते हुए) शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए" आश्रय कर लागू करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया।

(ग) "आश्रय कर" लागू करने पर निर्णय लेना और एतदर्थ मानदण्ड का निर्धारण करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का काम है। भारत सरकार द्वारा एकत्रित की जाने वाली वार्षिक राशि हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

सरकारी मकानों के लिए प्रतीक्षा सूची

1081. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने सरकारी कर्मचारी इस समय सरकारी मकानों के लिए प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) इन कर्मचारियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या योजनाएं बनायी जा रही हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में सरकारी मकानों के निर्माण से सम्बन्धित अनुमोदित प्रस्तावों में किस-किस वर्ग के लिए कितने-कितने मकानों के निर्माण का प्रावधान है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि नये प्रस्तावों के अनुरूप बनाये जा रहे मकानों में टाइप IV और ऊपर के मकान हैं; यदि हां, तो टाइप III और नीचे के मकानों का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ यू. वेंकटेस्वरलू): (क) सामन्य पूल रिहायशी वास के आवंटन हेतु आवेदन प्रति बंधित आधार पर प्रति दो वर्षों के बाद पात्र सरकारी कर्मचारियों से मांगे जाते हैं। आवंटन वर्ष 1.6.98 से 31.12.98 तक दिल्ली में विभिन्न टाइपों के मकानों हेतु 1.7.97 तक कुल 46498 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) वर्ष 1997-98 से शुरू हो रही नौवीं योजना के प्रस्तावों में सामान्य पूल रिहायशी आवास स्कीम हेतु 500 करोड़ रू॰ की राशि निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत के विभिन्न शहरों में उपरोक्त योजना अवधि के दौरान लगभग 10,000 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली सहित विभिन्न शहरों में इस समय निर्माणाधीन टाइपवार मकानों की संख्या निम्नलिखित है:—

टाइप	संख्या	टाइप	संख्या
I	520	IV	484
II	864	V	382
III	984	VII	07

Shops in Central Government Housing Complex, Vasant Vihar

1082. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have constructed some shops in the Central Government Housing Complex, Vasant Vihar, New Delhi; if so, whether the same have been allotted;

(b) if not, since when these have been lying vacant and the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the cost of lease of these shops is so high that the people are finding it difficult to make a bid; and

(d) what is the loss to the exchequer due to non-allotment of shops and by when these are likely to be allotted?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बिहार में शहरी युवाओं को रोजगार

1083. **श्री जनार्दन यादव:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के विभिन्न शहरों में कितने युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है;

(ख) शहरी बेरजोगारों को किन-किन योजनाओं से रोजगार मिला है; और

(ग) बिहार के बांका, गोड्डा, देवघर, दुमका और जमुई जिलों में वर्ष 1996-97 और वर्ष 1997-98 में अब तक कितने शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू.वेंकटेश्वरलू): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके नाम हैं—नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

नेहरू रोजगार योजना: वर्ष 1989 से शहरी लघु उद्यम योजना (सूमे) तथा शहरी मजदूरी रोजगार योजना (सूवे) चलाई जा रही है जिनका लक्ष्य बिहार सहित सारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली शहरी निर्धनों को स्व-रोजगार तथा मजदूरी-रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। 1989 से 30.6.97 तक बिहार में सूमे के अन्तर्गत 22,192 लाभार्थियों को सहायता दी गई है तथा सूवे के तहत 41.16 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।

प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम: नवंबर, 1995 में आरम्भ की गई इस योजना का एक घटक स्व-रोजगार है। बिहार में 50,000 से 1,00,000 तक की आबादी वाले 28 शहरी समूह इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार से अब तक किसी प्रगति की सूचना नहीं मिली है।

(ग) इस विभाग द्वारा योजनाओं की निगरानी क्षेत्रीय अथवा जिला स्तर की बजाय राज्य स्तर पर की जाती है।

Setting up of Directorate of Urban Transport

1084 SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up Directorate of Urban Transport in all the State, particularly in Rajasthan and Orissa, and during the Ninth Five Year Plan period, keeping in view the increasing transport poblems in big cities as well as urgent need for proper planning of routes;

(b) if so, what remedial steps Government have taken so far or are likely to